भारत सरकार
योजना मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4246
दिनांक 18.03.2026 को उत्तर देने के लिए

सतत विकास लक्ष्य

4246. श्री कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2020 से नीति आयोग के 'एसडीजी इंडिया' सूचकांक के अंतर्गत कर्नाटक की रैंकिंग और समग्र स्कोर संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दक्षिण कन्नड़ जिले के लिए उपलब्ध जिला-स्तरीय विस्तृत विश्लेषण का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन विशिष्ट सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और संकेतकों का ब्यौरा क्या है जिनमें कर्नाटक का प्रदर्शन निरंतर राष्ट्रीय औसत से नीचे रहा है तथा मूल्यांकन रिपोर्टों में उक्त प्रदर्शन के लिए किन कारणों की पहचान की गई है;

(ग) वर्ष 2020 से दक्षिण कन्नड़ जिले में एसडीजी में तेजी लाने की पहलों के लिए केंद्र और राज्य द्वारा आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) गरीबी उन्मूलन, लैंगिक समानता, स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूल कार्रवाई से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के प्रदर्शन में सुधार के उद्देश्य से उक्त जिले में कार्यान्वित की गई परियोजनाओं या योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पंचायत स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित क्षमता निर्माण कार्यशालाओं, जागरूकता अभियानों और नागरिक समाज के साथ की गई साझेदारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया सूचकांक के आधार पर कर्नाटक के समग्र स्कोर और रैंकिंग निम्नानुसार है:

	एसडीजी इंडिया सूचकांक 2020-21	**एसडीजी इंडिया सूचकांक 2023-24**
समग्र स्कोर	72	75
रैंक	6	8

यह सूचकांक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के स्तर पर कार्य निष्पादन का आकलन करता है, और जिला-स्तरीय विभाजन एसडीजी इंडिया सूचकांक रूपरेखा का हिस्सा नहीं है।

(ख) एसडीजी इंडिया सूचकांक 2023-24 के अनुसार, कर्नाटक का समग्र स्कोर 75 है, जो राष्ट्रीय औसत 71 से अधिक है। एसडीजी 15 (भूमि पर जीवन) में कर्नाटक का स्कोर 70 है, जबकि राष्ट्रीय औसत 75 है। एसडीजी इंडिया सूचकांक का उद्देश्य प्रगति की निगरानी करना, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना और सहकारी एवं प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देते हुए सभी क्षेत्रों में सुधार को प्रोत्साहित करना है। प्रदर्शन में भिन्नता के कारणों को चिन्हित करना भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

(ग) एवं (घ) कर्नाटक सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दक्षिण कन्नड़ जिले में विभिन्न योजनाएँ जैसे विकसित भारत - रोजगार और आजीविका हेतु गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) (पूर्ववर्ती महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (मनरेगा), जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, समग्र शिक्षा अभियान, स्वयं सहायता समूहों के लिए संजीवनी सामुदायिक निवेश कोष आदि कार्यान्वित की जा रही हैं। योजना-वार आवंटित निधि का विवरण अनुलग्नक में प्रस्तुत किया गया है।

(ङ) संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के तहत, पंचायती राज मंत्रालय पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबीएंडटी) के लिए विभिन्न श्रेणियों के तहत जैसे कि सामान्य अभिविन्यास और पुनश्चर्या प्रशिक्षण, विषयगत प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण और पंचायत विकास योजना पर प्रशिक्षण सम्बन्धी सहायता प्रदान करता है। इन क्षमता निर्माण पहलों ने ग्राम पंचायत विकास योजनाओं (जीपीडीपी) की तैयारी और कार्यान्वयन में विशेष रूप से सहभागी योजना बनाने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की क्षमता को मजबूत किया है। संशोधित आरजीएसए के शुभारंभ के बाद से कर्नाटक राज्य में 11,57,048 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।

अनुलग्नक

सतत विकास लक्ष्यों के संबंध में श्री कसान बृजेश चौटा द्वारा दिनांक: 18.03.2026 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4246 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

दक्षिण कन्नड़ में सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित पहलों के लिए आवंटित/जारी की गई धनराशि (2020-2025)

वर्ष	कार्यक्रम	राशि	निधि स्रोत	उद्देश्य (एसडीजी लिंक)
2020-21	एमजीएनआरईजीए	181 करोड़ रुपए	ग्रामीण विकास मंत्रालय	ग्रामीण रोजगार और गरीबी उन्मूलन (एसडीजी-1)
2021-22	जल जीवन मिशन	142 करोड़ रुपए	जल शक्ति मंत्रालय	ग्रामीण परिवारों को पेयजल आपूर्ति (एसडीजी-6)
2022-23	स्थानीय निकायों के लिए वित्त आयोग अनुदान	96 करोड़ रुपए	वित्त मंत्रालय, भारत सरकार	स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और स्थानीय अवसंरचना (एसडीजी-11, एसडीजी-13)
2023-24	पीएम-आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन	24.7 करोड़ रुपए	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना (एसडीजी-3)
2024-25	आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का विस्तार	80 करोड़ रुपए	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	124 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का निर्माण (एसडीजी-3)

2024-25	स्वयं सहायता समूह के लिए संजीवनी सामुदायिक निवेश कोष	70 करोड़ रुपए	कर्नाटक सरकार (केएसआरएलपीएस)	महिलाओं की आजीविका और सूक्ष्म उद्यम विकास (एसडीजी-5)

*****